भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1432

उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

वैश्विक शीर्ष-100 रैंकिंग में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान

†1432. **सुश्री सयानी घोष:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से प्रमुख वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग जैसे कि क्यूएस, टाइम्स हायर एजुकेशन और एआरडब्ल्यूयू के शीर्ष 100 पदों के भीतर स्थान पाने वाले भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों सहित) का वर्ष-वार, रैंक-वार और रैंकिंग एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई बार-बार की नीतिगत घोषणाओं के बावजूद हाल के वर्षों में बहुत कम या कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 100 में निरंतर अपना स्थान बरकरार नहीं रख पाया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित भारतीय संस्थानों के शीर्ष 100 वैश्विक रैंकिंग से निरंतर स्थान नहीं बना पाने या गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 'इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस' योजना के शुभारंभ से अब तक इसके तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का संस्थान-वार ब्यौरा और प्रत्येक संस्थान द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): भारत सरकार ने देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का प्रावधान, अनुसंधान और नवाचार तंत्र को सुदृढ़ करना तथा उद्योग-अकादमिक संपर्क को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल हैं।

उक्त पहलों से क्यूएस वर्ल्ड विश्वविद्यालय रैंकिंग (क्यूएस डब्ल्यूयूआर) जैसी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। क्यूएस

डब्ल्यूयूआर 2026 में कुल 54 भारतीय संस्थानों को रैंक प्राप्त हुई है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है, जो क्यूएस डब्ल्यूयूआर वर्ष 2015 में 11 संस्थानों से बढ़कर क्यूएस डब्ल्यूयूआर वर्ष 2026 में 54 संस्थानों तक पहुँच गया है। आठ भारतीय संस्थानों को पहली बार रैंकिंग मिली है, जो इस संस्करण में किसी भी देश के लिए जी 20 और वैश्विक रूप से दोनों में सर्वाधिक संख्या है । भारतीय संस्थानों के प्रदर्शन सहित अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग संबंधी विवरण संबंधित रैंकिंग एजेंसियों द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।

वर्ष 2014 से, तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और मानविकी के क्षेत्रों में नए केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों (सीएचईआई) की स्थापना करके उच्चतर शिक्षा पारिस्थितिकीय वृद्धि है। सीएचईआई से यह आशा की जाती है कि वे इस क्षेत्र के अन्य संस्थानों को अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए आदर्श संस्थानों के रूप में कार्य करेंगे। वर्ष 2014 से अब तक 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), 8 केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयू), 8 भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) और 1 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) स्थापित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय ने क्रमशः राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के माध्यम से मज़बूत प्रत्यायन तथा रैंकिंग तंत्र बनाए हैं। वर्ष 2015 में शुरू हुए एनआईआरएफ ने प्रति वर्ष इंडिया रैंकिंग प्रकाशित की है, जिसने भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) को अधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण में परिवर्तित कर दिया है। एनबीए ने परामर्श संबंधी कार्यशालाएँ भी आयोजित की हैं, जिनमें सर्वोत्तम पद्धतियाँ साझा की जाती हैं और भारतीय एचईआई को अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भाग लेने के तरीकों तथा प्रक्रिया से परिचित कराया जाता है।

(घ): शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2017 में सार्वजनिक और निजी श्रेणी के 10-10 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) का दर्जा प्रदान करने तथा उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में उभरने में समर्थकारी विश्व स्तरीय संस्थान योजना शुरू की थी। अब तक बारह संस्थानों को आईओई के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनमें 08 सार्वजनिक श्रेणी के संस्थान जैसे-आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बैंगलोर, बीएचयू वाराणसी, हैदराबाद विश्वविद्यालय, और दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल हैं, तथा 04 निजी श्रेणी के संस्थान जैसे - बिट्स पिलानी, मणिपाल एकेडमी ऑफ़ हायर एजुकेशन, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एवं शिव नादर यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा शामिल हैं। इस योजना के तहत केवल सार्वजनिक संस्थानों को निधियाँ प्रदान की जाती हैं। योजना शुरू होने के बाद से 08 सार्वजनिक संस्थानों के लिए लगभग 6198.99 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है।

*****